



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2007/श्रावण 3, 1929

No. 153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2007/SRAVANA 3, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 जुलाई, 2007

सं. टीएएमपी/13/2006-वीसीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से वीसीटीपीएल के बर्थ में निष्क्रिय खड़े रहने वाले पोत के लिए दण्डात्मक प्रभार की वसूली के लिए इसके दरमान में शर्त शामिल करने के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/13/2006-वीसीटीपीएल

विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

आदेश

(जून, 2007 के 28वें दिन पारित)

यह मामला शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से वीसीटीपीएल के बर्थ में निष्क्रिय खड़े रहने वाले पोत के लिए दंडात्मक प्रभार की वसूली के लिए इसके दरमान में शर्त शामिल करने के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 28 फरवरी, 2007 से संबंधित है।

2. वीसीटीपीएल ने शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से इसके बर्थ में पोत के निष्क्रिय खड़े रहने पर रु. 10,000 प्रति घंटा अथवा उसका भाग दंडात्मक प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया है। इसने अपने पहले किए गए निवेदनों की अभिपुष्टि करने के लिए पोतों की सूची और जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2005 अवधि के लिए पोत/शिपिंग लाइनों के कारण इसके टर्मिनल में विलम्ब की अवधि भेजी है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार वीसीटीपीएल का प्रस्ताव वीपीटी और संबद्ध प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। विशाखापत्तनम कंटेनर लाइन्स एसोसिएशन (वीसीएलए) से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीसीटीपीएल को अग्रेषित की गई थी। वीसीटीपीएल ने वीसीएलए की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

4. इस मामले में विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध होंगे।

5. तत्पश्चात, वीसीटीपीएल ने अपने दरमान की सामान्य समीक्षा के लिए फरवरी, 2007 में एक पृथक प्रस्ताव दाखिल किया था। उक्त प्रस्ताव में, इसने शिपिंग लाइनों पर आरोप्य कारणों से 2 घंटे से अधिक अथवा उसके भाग के लिए इसके बर्थ में निष्क्रिय खड़े होने वाले कंटेनर

पोतों पर रु. 5000 प्रति घंटा की वसूली का प्रस्ताव किया है। वीसीटीपीएल ने भी स्पष्ट किया है कि प्रशुल्क समीक्षा प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधित दर इसके पूर्ववर्ती प्रस्ताव में रु. 10,000 प्रति घंटा की प्रस्तावित दर का अधिक्रमण करती है।

6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 12 जून, 2007 को विशाखापत्तनम पत्तन न्यास परिसर में वीसीटीपीएल के प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव के साथ की गई थी। टर्मिनल में निष्क्रिय खड़े होने वाले कटेनर पोतों के लिए प्रस्तावित संशोधित प्रशुल्क का वीसीटीपीएल के सामान्य समीक्षा प्रस्ताव में विश्लेषण किया गया है जिस पर अलग से विचार किया जा रहा है। चूंकि प्रस्तावित प्रशुल्क मद संशोधित और सामान्य समीक्षा प्रस्ताव में शामिल की गई है, इसलिए इस मामले पर अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

7. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, यह मामला अतिरिक्त रूप में बंद कर दिया गया है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007/असा.]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd July, 2007

No. TAMP/13/2006-VCTPL.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Visakha Container Terminal Private Limited (VCTPL) for inserting a conditionality in its Scale of Rates for levy of penal charge for vessel idling at its berth for reasons attributable to shipping lines as in the Order appended hereto.

#### SCHEDULE

Case No. TAMP/13/2006 - VCTPL

Visakha Container Terminal Private Limited

Applicant

#### ORDER

(Passed on this 28th day of June, 2007)

This case relates to the proposal dated 28 February, 2007 from Visakha Container Terminal Private Limited (VCTPL) for inserting conditionality in its Scale of Rates for levy of penal charge for vessel idling at its berth for reasons attributable to shipping lines.

2. The VCTPL has proposed to levy penal charge of Rs. 10,000 per hour or part thereof for idling of vessel at its berth for reasons attributable to the shipping lines. It has furnished a list of vessels and the duration of delay at its terminal on account of vessel/shipping lines for the period July 2003 to December 2005 to substantiate the submissions made earlier.

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of VCTPL was forwarded to VPT and to the concerned user organisations for their comments. The comments received from the Visakhapatnam Container Lines Association (VCLA) were forwarded to VCTPL as feedback information. The VCTPL has responded to the comments of the VCLA.

4. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>

5. The VCTPL has subsequently filed a separate proposal for a general review of its Scale of Rates in February 2007. In the said proposal, it has proposed to levy Rs. 5000 per hour on container vessels idling at its berth for more than 2 hours or part thereof for reasons attributable to shipping lines. The VCTPL has also clarified that the revised rate proposed in the tariff review proposal supercedes the proposed rate of Rs. 10,000 per hour in its earlier proposal.

6. A joint hearing in this case was held on 12 June, 2007 at the Visakhapatnam Port Trust premises along with the tariff revision proposal of the VCTPL. The revised tariff proposed for container vessels idling at the terminal has been analysed in general review proposal of the VCTPL which is being considered separately. Since the proposed tariff item has been revised and included in the general review proposal, it is not necessary to pursue this case separately.

7. In the result, and for the reasons given above, this case is closed as superfluous.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT III/IV/143/2007/Extty.]